पंजाब सरकार

हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री, पंजाब

द्वारा

पंजाब विधान सभा में

वर्ष 2022-23 का

बजट पेश करते समय दिया गया

भाषण

27 जून, 2022

चण्डीगढ़

बजट 2022-23
हरपाल सिंह चीमा
वित्त मंत्री
का भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. मैं यहाँ 16 मार्च 2022 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी के नेतृत्व वाली आप सरकार का पहला बजट पेश करने आया हूँ। मुझे पंजाब के वित्त मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिलने पर गर्व है। यह और भी भाग्यशाली हो जाता है जब पूरा देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम सभी उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए महान बलिदानों के कारण लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठे हैं। मैं इस सरकार की ओर से उन्हें यह बजट समर्पित करता हूँ और पंजाब और इसके लोगों की भलाई के लिए उनके सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस के साथ योगदान देने का संकल्प लेता हूँ।

2. पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी में अपार विश्वास जताया है। इस बार लोगों ने 'बदलाव' के लिए वोट किया है। आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटों पर अभूतपूर्व बहुमत देने के लिए यह सरकार पंजाब की जनता की आभारी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने एक "रंगला पंजाब" बनाने का वादा किया है जो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास और समावेशिता का प्रतीक होगा।" बनाने का वादा किया है जो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास और समावेश का प्रतीक होगा। हम राज्य में भ्रष्टाचार, माफिया शासन को समाप्त करने और कानून व्यवस्था बहाल करने का अपना संकल्प दोहराते हैं।

3. पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को समझ चुकी है। यह पार्टी केवल बातों में विश्वास नहीं करती बल्कि गारंटी के रूप में अपना संकल्प प्रस्तुत किया है। माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में पार्टी ने दिल्ली में एक सफल और प्रभावी मॉडल पेश किया है। इसी तरह की पहलों को पंजाब में दोहराते हुए, हम को इसे एक समृद्ध राज्य बनाएंगे, जिस पर आने वाली पीढ़ियों को सदैव गर्व रहेगा।

4. इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे अंदर कुछ कर दिखाने और सेवा की भावना की गहरी प्रेरणा दी है; और यह भावना पदभार ग्रहण करने के पहले दिन से ही स्पष्ट हो गई है। हमारे महान गुरु साहिबों से प्रेरित होते हुए, शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह जी जिन्हों ने 23 साल की उम्र में स्वतंत्र भारत का सपना देखा और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी और भीम राव अम्बेडकर के जीवन से निर्देशित, जिनका एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत का सपना हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस विधानसभा बजट के माध्यम से हमारी सरकार के कल्याण और विकास का एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पिछले 100 दिनों की बहुत ही कम अवधि में अनेक उपाय किए हैं और ऐसे फैसले लिए हैं जिनका पंजाबियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

5. महोदय, आप सरकार सुशासन का एक शानदार मॉडल विकसित करेगी और एक स्वच्छ, कुशल और प्रभावी प्रशासन का वादा करेगी। हमारा शासन मॉडल सहभागी, जवाबदेह होगा और समानता और समावेश सुनिश्चित करेगा। मैं अपनी सरकार की ओर से वादा करता हूँ कि जब पंजाब आगे बढ़ेगा तो पंजाब की आबादी या क्षेत्र का कोई भी हिस्सा पीछे नहीं रहेगा।

6. माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के सक्षम और गतिशील नेतृत्व में, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी के लिए एक

"भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन" शुरू की गई है, जिससे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पंजाब के लोग इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। जग-जाहिर है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपी अपने ही कैबिनेट मंत्री को बिना देरी किए हटाया और कानूनी कार्यवाही शुरू की और अब तक 28 मामलों में 45 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आम जनता के लिए भ्रष्टाचार और उनके द्वारा सामना किए जाने वाले किसी भी कदाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं हर पंजाबी से अपील करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त और माफिया मुक्त पंजाब बनाने के लिए पंजाब सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों।

7. यह अभूतपूर्व है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के कुछ दिनों के भीतर अपने कई चुनावी वादों को पूरा किया है। पुरानी सरकारें अपने कार्यकाल की समाप्ति से कुछ समय पहले कुछ सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी करती थीं और अधिकांश भर्तियां कुछ कानूनी बाधाओं के कारण पूरी नहीं हो पाती थीं परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार ने 26,454 कर्मचारियों की नई भर्ती को मंजूरी दी और यह प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा सरकार ने 36,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का भी अहम फैसला लिया है। हमारी सरकार पंजाब के युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उनकी क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ है। हमने कैनेडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों की ओर ब्रेन ड्रेन की रोकथाम और पंजाब में ही रोजगार के अवसरों के लिए उपयुक्त संसाधनों के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने का बीड़ा उठाया है।

8. माननीय अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली गारंटी को पूरा करते हुए पंजाब के सभी नागरिकों को 1 जुलाई, 2022 से 300 यूनिट घरेलू बिजली की आपूर्ति नि:शुल्क उपलब्ध करवाने का फ़ैसला किया है। इस से अतिरिक्त बिजली बिलों से जूझ रहे

पंजाबियों के लिए यह एक बड़ी राहत मिलेगी। मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस योजना को वित्तपोषित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

9. हम वादा करते हैं कि हम अपना वादा निभाएंगे कि हम सरकारी खजाने का एक-एक पैसा केवल लोगों के कल्याण के लिए खर्च करेंगे और कहीं नहीं। इसी विचार से प्रेरणा लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने 'एक विधायक एक पेंशन' की शुरुआत की है, पहले कई पूर्व विधायकों को कई (एक से ज्यादा) पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब इस फैसले से सालाना जनता के पैसे में करीब 19.53 करोड़ रुपये की बचत होगी।

10. माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान को एहसास है कि अगर कृषि और किसान विफल हो जाते हैं तो पंजाब सफल नहीं हो सकता। सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार पहले ही धान की सीधी बुवाई को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा कर चुकी है, जो टिकाऊ खेती और पानी की बचत तकनीकों को अपनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा मूंग की दाल को एम.एस.पी पर खरीदने का ऐतिहासिक फैसला पहले ही लिया जा चुका है। भाषण के अगले भाग में इन पहलकदमियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

11. आज, मैं डिजिटल रूप से मुझे बजट पेश करने की अनुमति देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाषण के बाद सभी बजट दस्तावेज मोबाइल एप पर उपलब्ध होंगे। यह पहल 21 लाख रुपये की वार्षिक बचत होगी और इससे भी अधिक आश्वस्त करने वाली बात यह है कि इसने 800 से अधिक पेड़ों कटने से को बचाया है।

12. यह बजट हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के फ़लसफ़े का प्रतिबिंब है, जो मानते हैं कि लोगों की आवाज सुने बिना दी गई

'लोकनीति' का असफ़ल होना तय है। यह पहला मौका है जब सरकार ने बजट तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर आम जनता से मशविरा किया है। बजट बनाने की कवायद, जो सरकारी कार्यालयों की दीवारों तक ही सीमित थी, इन सीमाओं से आगे निकल गई और प्रमुख हितधारकों . "पंजाब के लोग" तक पहुंच गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों, उद्योगपतियों, व्यापार संघों, युवाओं, महिलाओं और जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझावों की पेशकश की गई और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस बजट में पंजाब के लोगों की संभावित आकांक्षाओं को शामिल किया गया है और यह बजट जनता द्वारा तैयार किया गया "जनता बजट" है।

13. मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमें ईमेल, पत्र और ज्ञापन के माध्यम से पोर्टल पर 20,384 सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से 72.70% सुझाव 31 से 40 वर्ष (45.42%) आयु वर्ग के पुरुषों से और 27.3% सुझाव महिलाओं से 31 से 40 वर्ष (48.2%) आयु वर्ग में प्राप्त हुए हैं। इस बजट से लोगों की उम्मीदों पर करीब से नजर डालने के लिए सरकार ने जिला स्तरीय बैठकें भी की हैं। इन दौरों में सभी 23 जिलों को शामिल किया गया और ढेर सारे सुझाव प्राप्त हुए। हमें लुधियाना, पटियाला, फाजिल्का, बठिंडा, मंडी गोबिन्दगढ़, बटाला, संगरूर और अमृतसर से जबरदस्त प्रोत्साहन मिला।

14. अध्यक्ष महोदय, पहले वर्ष में हमारा ध्यान तीन पक्षीय होगा, अर्थात

- बिगड़ती वित्तीय स्थिति को बहाल करना और हमारे अपने राजस्व को बढ़ाकर बढ़ते ऋण को कम करना;
- सार्वजनिक निधियों के कुशल और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करके, फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाकर और मौजूदा योजनाओं में सुधार करके "कुशल राज्य प्रबंध" के वादे को पूरा करना; और
- किसी भी समाज की दो नींवों अर्थात स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

15. अब मैं इस प्रतिष्ठित सदन को बताना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए का बजट में हमारे राज्य के वित्त के तथ्य शामिल हैं और सरकार का दृष्टिकोण लोकतंत्र के मूल सिद्धांत "लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए" पर खरा उतरता है।

हमारी वर्तमान स्थिति

माननीय अध्यक्ष महोदय,

16. सरकार ने इस प्रतिष्ठित सदन के सामने राज्य वित्त पर एक श्वेत पत्र के माध्यम से पंजाब के लोगों को राज्य वित्त की असली तस्वीर पेश की है। पिछली सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए श्वेत पत्रों से एक बड़ा बदलाव आया है, जो अपने दृष्टिकोण में निराशावादी थे और इसे समाधान निकालने और भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करते थे। हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया श्वेत पत्र एक ओर राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है, और दूसरी ओर यह पंजाब को उसके शीर्ष स्थान पर वापस लाने के संभावित समाधान और पहलकदमियों के बारे में बात करता है, जो की जानी चाहिएं।

17. श्वेत पत्र यह स्पष्ट करता है कि पंजाब ने दशकों से वित्तीय नासमझी देखी है। पिछली सरकारों ने अब तक आसमान छू रहे गैर-उत्पादक राजस्व व्यय को कम करने की केवल बातें ही की थीं। पंजाब ने पूंजी और सामाजिक क्षेत्र के निवेश में गिरावट देखी है, जो भविष्य के विकास के लिए जरूरी है, और सच यह है कि कर और गैर-कर राजस्व बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

18. सही दृष्टिकोण से देखें तो, पंजाब का ऋण वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2.63 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा राज्य एजेंसियों /पीएसयू'ज़/ बोर्डों/ निगमों पर लगभग 55,000 करोड़ रुपए का ऋण है, जिसमें से लगभग 22,250 करोड़ रुपए की गारंटी राज्य सरकार ने दी है। पिछले पांच वर्षों में यानी वित्तीय वर्ष 2016-17 से

वित्तीय वर्ष 2021-22 तक राज्य का ऋण 44.23 फीसदी बढ़ा है।

19. जहां पंजाब लंबे समय से देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे रहा है, वहीं अब वह अन्य राज्यों से भी पिछड़ रहा है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय रैंकिंग में पहले स्थान से फिसल कर 11वें स्थान पर आ गई है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है।

20. कुल केंद्रीय हस्तांतरण (अर्थात केंद्रीय करों का हिस्सा + केंद्र से प्राप्त अनुदान) जो वित्त वर्ष 2011-12 में कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 22.85% था, वित्त वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों का दोगुना होकर 46.11% हो गया है। राज्य का अपना कर राजस्व उपरोक्त अवधि में 71.82% से घटकर 47.79% हो गया है, जो राज्य की आंतरिक रूप से संसाधन जुटाने की क्षमता में उल्लेखनीय गिरावट और केंद्र सरकार से प्राप्त राज्य के वित्त पर उच्च निर्भरता को दर्शाता है। वैट, राज्य आबकारी, वाहन कर, टिकट और पंजीकरण, और खनन से प्राप्त हुआ राजस्व अपेक्षा से कम रहा है, जबकि यह उच्च राजस्व अर्जित करने वाले क्षेत्रों में बाजार की विफलता और दोषपूर्ण नीतियों की कहानी कहता है।

21. पिछली सरकार द्वारा राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।यह कहना गलत नहीं होगा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रणाली को समाप्त करने की तैयारी में योजना और राजस्व को मज़बूत करने के प्रयासों की कमी ने राज्य को समझौता करने की स्थिति में ला दिया है। चूंकि जीएसटी मुआवजा प्रणाली जून, 2022 में समाप्त हो रही है, इसलिए राज्य सरकार अकेले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14,000-15,000 करोड़ रुपए का भारी घाटा वहन करेगी। यह राज्य के लिए "तेजी से गिरावट" की ओर जाने की स्थिति है।

22. पंजाब को उसके गौरवशाली दिनों में वापस ले जाने के लिए, खर्च की प्रतिबद्धताओं पर गंभीरता से पुनर्विचार करने के साथ-साथ प्रत्यक्ष राजस्व बढ़ाने के उपाय करने का समय आ गया है। वित्तीय स्थिरता, सतत विकास और ऋण निर्भरता को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के उपेक्षित स्तरों के साथ-साथ संरचनात्मक और नीतिगत पहल की आवश्यकता है।

23. "बीते दशक" की भरपाई के लिए, राज्य को बहुत सावधानी से उधार लेना होगा और उच्च गुणवत्ता वाले पूंजीगत व्यय को बनाने में भारी निवेश करना होगा। इससे अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति के चक्र में तेजी आएगी। उम्मीद है कि पंजाब अपनी विकास दर को बढ़ाने और आने वाले वर्षों तक इसे बनाए रखने में सक्षम होगा।

वर्तमान आर्थिक स्थिति

माननीय अध्यक्ष महोदय,

24. अब, मैं इस सदन को राज्य के कुछ प्रमुख आर्थिक संकेतकों से परिचित कराना चाहूँगा। वर्ष 2021-22 के लिए, पंजाब की जीएसडीपी वर्तमान कीमतों पर 5,73,763 करोड़ रुपए बनी रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.32% की वृद्धि थी, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि 8.90% रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीएसडीपी 6,29,834 करोड़ रुपये आंकी गई है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9.77% की वृद्धि है। पंजाब की अर्थव्यवस्था में, कृषि क्षेत्र अभी भी सकल घरेलू उत्पाद में 24.83 % का महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान क्रमश: 50.63% और 24.54% है। पंजाब का प्रभावी बकाया कर्ज जीएसडीपी (2021-22) के 45.88 करोड़ पर खड़ा है जो वर्ष 2016-17 से 44.23% की वृद्धि दर्शाता है।

सार्वजनिक वित्त को मजबूत करना

25. मौजूदा हालात को देखते हुए आप सरकार वित्तीय सूझबूझ की जरूरत से पूरी तरह वाकिफ है। मैं इस पावन सदन को राज्य के वित्त प्रबंधन में वित्तीय विवेक और दक्षता लाने के लिए उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताना चाहता हूँ:

1. **वित्तीय जोखिम विवरण का आरंभ:** राज्य को कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है, यह बजट के साथ.साथ वित्तीय जोखिम विवरण प्रस्तुत करने का एक प्रमुख प्रयास है ताकि इसे लिखित रूप में लाया जा सके। इस ब्यान से पारदर्शिता बढ़ेगी; सार्वजनिक वित्त के सुदृढ़ प्रबंधन में सहायता और भविष्य में उचित जोखिम शमन उपायों को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

2. **लिंग आधारित बजटीय दिशानिर्देश:** मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुशासन और समावेशी विकास के सिद्धांतों के आधार पर, सरकार इस वर्ष एक लिंग उत्तरदायी बजट दिशानिर्देश जारी करेगी जो सामाजिक परिवर्तन लाने और भेदभाव को समाप्त करने के लिए लैंगिक समानता और इसे मुख्यधारा में एकीकृत करने के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु रणनीति तैयार करेगी।

3. **विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित वित्तीय और संस्थागत लचीलापन (बीफ़ेयर) परियोजनाएं:** राज्य ने बीफ़ेयर परियोजना के तहत विश्व बैंक से हाथ मिलाया है। यह संस्थागत क्षमताओं और जवाबदेही को मजबूत करने वाला एक व्यापक ढांचा पेश करेगा; सुशासन के लिए बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण और अन्य सुधार उपायों का समर्थन करेगा । लचीलेपन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए संस्थागत सुधार लाने के लिए 1655 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली

परियोजना को 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इस कुल परियोजना लागत में से पंजाब सरकार 500 करोड़ रुपये (लगभग) का योगदान देगी।

4. **टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट:** अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए, मैं राज्य में एक टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। यह यूनिट करदाता के संचार और सुविधा के माध्यम से जीएसटी के तहत कर अनुपालन में सुधार के लिए वित्त विभाग को तैयार करेगा; और विभाग में रुझानों और प्रतिमानों को प्राप्त करने के लिए कर विश्लेषण क्षमताओं को मजबूत करेगा, जिससे कमजोर और मजबूत क्षेत्रों का उत्थान होगा।

5. **समेकित सिंकिंग फ़ंड:** राज्य के वित्त को मजबूत करने और भविष्य में ऋण प्रतिबद्धताओं के निपटान के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाने के लिए, हमारी सरकार ने पहले दो महीनों के भीतर राज्य के समेकित सिंकिंग फ़ंड (सीएसएफ) में 1000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जिससे संचयी योगदान 3988 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछली सरकारें इन सभी वर्षों में केवल 2988 करोड़ रुपए का योगदान दे पाई थीं।

बजट 2022-23

माननीय अध्यक्ष महोदय,

26. अब, मैं आपके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ। इन अनुमानों को पंजाब के आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे - स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ चिन्हित क्षेत्रों और लक्षित व्यय पर विशेष ध्यान देने के साथ पंजाब के पुनर्निर्माण के लिए तैयार किया गया है। मेरी अगली घोषणाएं भी इसकी साक्षी होंगी।

27. मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 1,55,860 करोड़ रुपये के बजट व्यय का प्रस्ताव रखता हूँ, जो कि वर्ष 2021-22 (संशोधित अनुमान) से 14.20% की वृद्धि है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः 199. % और 378.% रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीएसडीपी के लिए प्रभावी बकाया ऋण 4523.% होने का अनुमान है।

28. मैं राज्य के राजस्व व्यय को 1,07,932 करोड़ रुपए पर अनुमानित रखने का प्रस्ताव रखता हूँ जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 5.35% की वृद्धि है। इसमें से 66,440 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध व्यय के लिए प्रस्तावित हैं, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.10% की वृद्धि है। इसके मुख्य कारण छठे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन, विरासत में मिले ऋण और संबंधित ब्याज का भुगतान हैं।

29. पूंजीगत व्यय बजट अनुमान 10,981 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.95% की वृद्धि दर है। यह भविष्य में निवेश करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है क्योंकि पूंजीगत संपत्ति और बुनियादी ढांचे का अर्थव्यवस्था पर कई गुणा प्रभाव पड़ता है।

30. अब मैं आप सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप निम्नलिखित क्षेत्रीय विभाजन और नई पहलकदमियों का प्रस्ताव रखता हूँ।

शिक्षा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं यहाँ डॉ बीआर अंबेडकर को उद्धृत करता हूँ जिन्होंने कहा था कि "शिक्षा एक शेरनी का दूध है जो कोई भी इसे पीएगा उसकी आवाज बुलंद होगी।"

31. यह सरकार शिक्षा को मानवता की वृद्धि और विकास की सीढ़ी मानती है। हम मानते हैं कि शिक्षा रोजगारपरकता, चरित्र निर्माण, गरीबी में कमी और सामाजिक कल्याण की नींव है। इतिहास गवाह है कि लाला लाजपत राय जी, शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह जी, सरदार करतार सिंह सराभा जी, शहीद उधम सिंह जी और ऐसे कई अन्य गुमनाम नायकों के नेतृत्व में पंजाब स्वतंत्रता संग्राम में अगुआ रहा है। इसी तरह, शिक्षा के प्रति हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब वर्ष 2047 (स्वतंत्रता के 100वें वर्ष) में राष्ट्र की समृद्धि की दिशा में अग्रणीय बने। सबसे उन्नत शिक्षा से लैस हमारा समाज, सबसे उन्नत तकनीक वाले किसान और सबसे कुशल प्रथाओं वाले उद्योगपति राष्ट्र को ऐसा नेतृत्व प्रदान करेंगे। इस उद्देश्य के साथ, 'आप' सरकार किफ़ायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां ध्यान **केवल** यत्नों पर **ही** नहीं बल्कि परिणामों पर भी होगा।

32. हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं जो न केवल मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ अत्याधुनिक स्कूल भवनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा, बल्कि स्कूल और कॉलेज के संस्थापकों यानी शिक्षकों/ प्रधानाचार्यों की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। मुझे यह घोषणा करते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए 16.27% का बजट प्रावधान किया गया है; इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा के लिए 47.84% और चिकित्सा शिक्षा में 56.60% की भारी वृद्धि की गई है। मैं वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू की जाने वाली निम्नलिखित नई पहलकदमियों को शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं:

33. **सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता:** कई सरकारी स्कूलों का रखरखाव बहुत खस्ता है। साफ-सफाई, पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, सफेदी, पंखे की

मरम्मत, रोशनी की व्यवस्था, सामान्य साफ-सफाई और छोटी-छोटी मरम्मत जैसी बुनियादी चीजों के अभाव में छात्र स्कूल जाने और सीखने से कतराते हैं। यह मूल रूप से धन की कमी, निर्णय लेने के केंद्रीकरण और स्कूल प्रमुखों/प्राचार्यों के अधिक व्यस्त रहने के कारण है। सरकार स्कूलों के एक समूह के लिए 'एस्टेट मैनेजर्स' नियुक्त करने का प्रस्ताव रखती है, ताकि प्रधानाध्यापक अपना ध्यान शिक्षा पर केंद्रित कर सकें और बुनियादी और आवश्यक मरम्मत पर तत्काल ध्यान दिया जा सके। इसके लिए मैं वित्त वर्ष 2022-23 में 123 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि हमारी सरकार अपने पहले वर्ष में इन मूलभूत मुद्दों का ध्यान रखेगी।

34. **शिक्षकों / स्कूल प्रमुखों / शैक्षिक प्रशासकों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, हमारी सरकार शिक्षण के गुणवत्ता पहलुओं और बेहतर बाल उन्मुख प्रशिक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों / प्रधानाचार्यों / प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित करने और क्षमता निर्माण का प्रस्ताव रखती है। मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित एजेंसियों / संस्थानों द्वारा अल्पकालिक और मध्यम अवधि के प्रशिक्षण के लिए 30 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

35. **विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अनुसंधान अध्ययन/कार्यक्रम मूल्यांकन/ प्रभाव विश्लेषण के लिए विशिष्ट एजेंसियां:** शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे स्थानांतरण नीति; स्मार्ट स्कूल नीति; पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब; अंग्रेजी बूस्टर क्लब आदि के प्रभाव और परिणामों के विश्लेषण के लिए सी.आर.आर.आई.डी/आई.डी.सी/पंजाब विश्वविद्यालय / एन.सी.ई.आर.टी / एन.आई.ई.पी आदि विशेष एजेंसियों/अनुसंधान संस्थानों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव रखती है। यह इन

कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए फीडबैक लूप प्रदान करेगा।

36. **स्कूलज़ ऑफ एमिनेंस:** हमारी सरकार छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। हमने 100 मौजूदा स्कूलों की पहचान की है जिन्हें "स्कूल ऑफ एमिनेंस" में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। ये स्कूल प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के संयुक्त स्कूल होंगे और इनमें डिजिटल क्लासरूम, पूरी तरह से सुसज्जित लैब, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रशिक्षित फैकल्टी जैसे उत्तम बुनियादी ढांचे होंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

37. **सरकारी स्कूलों में आधुनिक डिजिटल क्लासरूम की स्थापना:** शिक्षकों और प्रशिक्षकों को दूर-दराज के स्थानों में रहने वाले छात्रों से जुड़ने और विभिन्न प्रकार के वर्चुअल प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग करने में मदद करने के लिए, सरकार ने गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने और प्रशिक्षण को एक वर्चुअल इंटरैक्टिव अनुभव बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटली कनेक्टेड क्लासरूम लॉन्च करने का प्रस्ताव रखती है। । सरकार पहले चरण में 500 सरकारी स्कूलों में आधुनिक डिजिटल क्लासरूम स्थापित करने का प्रस्ताव रख रही है। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

38. **सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम की स्थापना:** सौर ऊर्जा का उपयोग करने से स्कूलों को अपने कार्बन फुटप्रिंट को 25% तक कम करने और अपनी ऊर्जा मांग का 70% पूरा करने में मदद मिल सकती है। सौर पैनलों के माध्यम से बिजली पैदा करना किफायती साबित हुआ है जिससे स्कूलों को अपने बिजली के बिल कम करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में राज्य के 19,176 सरकारी स्कूलों में से केवल 3,597 स्कूलों में ही

विभिन्न योजनाओं के तहत सोलर पैनल सिस्टम लगाए गए हैं। मैं चालू वित्त वर्ष में सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम लगाने की व्यापक योजना लाने और इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखता हूँ।

39. **सरकारी स्कूलों में चारदीवारी सहित बुनियादी ढांचे का उन्नयन:** हमारे स्कूल विशेष रूप से छात्राओं के लिए सुरक्षित और महफ़ूज़ स्थान होने चाहिएं। इसके अलावा, चल बुनियादी ढांचे और उपकरण, विशेष रूप से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी या नष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे सर्वेक्षण से पता चलता है कि अभी भी 2,728 ग्रामीण स्कूल और 212 शहरी स्कूल हैं जहाँ नई चारदीवारी की आवश्यकता है और 2,310 ग्रामीण स्कूल और 93 शहरी स्कूल हैं जहाँ चारदीवारी की तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। इस के अलावा पंजाब के हर ज़िले में अति-आधुनिक स्कूली बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस बजट में 424 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

40. **छात्रों के लिए वर्दी:** वर्तमान में सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक की सभी लड़कियों और एससी/एसटी/बीपीएल लड़कों को वर्दी प्रदान की जाती है। इस सरकार ने इस योजना को यूनीवर्सल योजना में बदलते हुए पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों और सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को वर्दी प्रदान करने का निर्णय लिया है और इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

41. **पंजाब युवा उद्यमी कार्यक्रम:** पंजाबी अपने उद्यमशीलता नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं लेकिन दुर्भाग्य से जब वे स्कूलों में थे हमारी शिक्षा प्रणाली ने अतीत में उद्यमशीलता कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। हमारा मानना है कि उद्यमिता कौशल हमारे समाज की ताकत का मुख्य स्तंभ है और इस मजबूत नींव पर हम आगे बढ़ने का

इरादा रखते हैं। पंजाब युवा उद्यमी कार्यक्रम एक स्टार्ट अप प्रोग्राम है जहां 11वीं कक्षा के छात्र व्यवसाय से संबंधित विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसे सरकार द्वारा 2000 रुपये प्रति छात्र की दर से आरंभिक राशि प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वित्तीय और नेतृत्व कौशल विकसित करना है, जिससे वे अपने भविष्य के करियर के बारे में जागरूक हो सकें। मैंने इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

42. आप सरकार शिक्षा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और जहां भी आवश्यक हो, अतिरिक्त बजटीय सहायता के साथ चल रही योजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगी, ऐसी ही योजनाओं की रूपरेखा नीचे दी गई है:

- **मिड डे मील:** वित्त वर्ष 2022-23 में 17 लाख छात्रों को मिड डे मील भोजन उपलब्ध कराने के लिए 473 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान) से 35% अधिक है।

- **समग्र शिक्षा अभियान:** वित्तीय वर्ष 2021-22 (संशोधित अनुमान) में इस वर्ष 1231 करोड़ रुपए की तुलना में 1351 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।

- **ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:** मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 67 करोड़ रुपए आरक्षित रखने का प्रस्ताव रखता हूँ।

- **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:** वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2.40 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 79 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

उच्च शिक्षा

43. इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 बताती है कि भारत में केवल 46.20% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं। दुर्भाग्य से पंजाब न तो रोजगार योग्य लोगों के शीर्ष प्रदानकर्ताओं की सूची में है और न ही रोजगारपरकता में। इस सरकार का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों को गतिशील, मांग-संचालित, गुणवत्ता के प्रति जागरूक, कुशल और दूरंदेशी बनाकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ध्यान न केवल अनुशासन आधारित शिक्षण पर दिया जाएगा बल्कि कौशल आधारित शिक्षण पर भी होगा।

44. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, प्राथमिक रूप से हमारी मातृभाषा पंजाबी को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य रूप से एक बहु अनुशासनिक शिक्षा प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। हालाँकि, यह अतीत में कुप्रबंधन का शिकार हो गया है और इसलिए इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए, मैं चल रहे वित्तीय संकट से निपटने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 200 करोड़ रुपए आवंटित करता हूँ।

45. **नौ नए पुस्तकालयों में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान:** मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में तरनतारन, बरनाला, लुधियाना, फाजिल्का, मलेरकोटला, मोगा, पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब और शहीद भगत सिंह नगर के 9 जिलों के सरकारी कॉलेजों के पुस्तकालयों में बुनियादी सुविधाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए 30 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

46. **विश्वविद्यालय शुल्क में छूट के लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति:** सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, आप सरकार ने छात्रवृत्ति राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शुल्क में रियायत के रूप में प्रदान की

जाएगी। मैं इस उद्देश्य के लिए 30 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

47. एन.सी.सी. सशस्त्र बलों में करियर का लॉन्च पैड रहा है, जिसके लिए पंजाबियों को जाना जाता है। पंजाब के एन.सी.सी. कैडेटों की संख्या में इजाफा हुआ है। एन.सी.सी. इकाइयां और प्रशिक्षण केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, और पंजाबी युवाओं को अनुशासित, देशभक्त और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं इस वर्ष राज्य के एन.सी.सी. इकाइयों और एनसीसी प्रशिक्षण केंद्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार और नई सुविधाओं के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

48. आप सरकार सभी सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नए अत्याधुनिक डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में शुरू में 95 करोड़ रुपए का आरंभिक आवंटन प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षा

49. हमारे छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और रोजगार योग्य लोगों का शीर्ष स्रोत राज्य बनाने के उद्देश्य से, इस सरकार का ध्यान कक्षा प्रशिक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप, क्षेत्र के दौरे और कौशल विकास परियोजनाओं के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर होगा। इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण और विस्तार पर मुख्य ध्यान देने के साथ तकनीकी शिक्षा के लिए 641 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

खेल और युवा सेवाएं

50. पंजाब नवोदित खिलाड़ियों का पालना था। यदि मैं कहूँ कि पंजाब के प्रत्येक गांव में अतीत में संभावित पदक विजेता थे तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अन्य राज्य ने

अपनी अभिनव खेल नीतियों के माध्यम से विश्व स्तर के खिलाड़ी पैदा करने में आगे बढ़े और जब कि पंजाब में किसी भी प्रभावी खेल नीति के अभाव में पंजाब के खिलाड़ियों को अन्य राज्यों के लिए खेले। हमारी सरकार का सपना है कि पंजाब को पहले की तरह फिर से उसी मुकाम पर लाया जाए। इस वर्ष, मैं नवोदित और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए दो नई योजनाओं का प्रस्ताव करना चाहता हूँ और इस उद्देश्य के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान करना चाहता हूँ।

51. सरकार ने लौंगोवाल, सुनाम (जिला संगरूर) में एक अति-आधुनिक स्टेडियम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और इसके लिए वर्ष के दौरान पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, खेल के स्तर को बढ़ाने के लिए मौजूदा स्टेडियमों को भी अपग्रेड किया जाएगा।

मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान

52. किसी भी देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए मेडिकल शिक्षा एक महत्वपूर्ण आधार है। मेडिकल कॉलेज पालना हैं, जिनमें विश्व स्तर के डॉक्टर पैदा करने की क्षमता है, जिनकी कमी भारत में हर गुजरते दिन के साथ महसूस की जा रही है। दूसरा, हम नहीं चाहते कि हमारे मेडिकल छात्र यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल का अध्ययन करें और इसलिए राज्य में सर्वोत्तम मेडिकल शिक्षा इको-प्रणाली प्रदान करने का वादा करें। इस उद्देश्य के साथ, हमारी सरकार ने संपूर्ण पंजाब को कवर करते हुए 5 साल की अवधि में 16 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जिस से राज्य में कालेजों की संख्या कुल मिला कर 25 हो जाएगी।

53. इस वर्ष, मैं मेडिकल शिक्षा के लिए 1033 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूँ जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 (आरई) की तुलना में 56.60% की वृद्धि है। मौजूदा राज्य सरकार के

मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन और इन कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि संत अतर सिंह राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान, जिला संगरूर में 100 एमबीबीएस सीटों वाला एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संत अतर सिंह राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान, मेडिकल कॉलेज संगरूर के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आरक्षण किया गया है।

54. हमारी सरकार का वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान साहिबजादा अजीत सिंह (एसएएस), नगर में अति-आधुनिक "पंजाब इंस्टिट्यूट ऑफ़ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज" स्थापित करने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य

अध्यक्ष महोदय,

"चंगी सेहत सब तों वड्डी दौलत है"

55. किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसके नागरिकों द्वारा समान, सस्ती और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पहुंच पर निर्भर करता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जेब से अधिक खर्च लोगों को गरीबी में धकेल रहा है।

56. मैं पंजाब के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बजट में इस सबसे जरूरी लेकिन बेहद उपेक्षित सेक्टर यानी हेल्थ सेक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पंजाब में कोई भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उसका इलाज न हो पाए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं, अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान

जी के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बनकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए की जाने वाली योजनाओं और पहलकदमियों का एक मजबूत रोडमैप तैयार कर रहा हूँ। मुझे 4731 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उच्चतम बजट का प्रस्ताव करते हुए खुशी हो रही है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 23.80% की वृद्धि है।

57. **मोहल्ला/पिंड क्लीनिक:** अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पंजाब के लोगों को भौगोलिक, लिंग, वर्ग, जाति, आयु, धर्म या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के बिना स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की "अंतिम मील डिलीवरी" प्रदान करने में विश्वास करती है। पंजाब की सदूर इलाकों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है ताकि नागरिक स्वयं को सम्मानजनक जीवन जीने की बुनियादी आवश्यकताओं के हकदार महसूस करें। यह सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को निम्नतम स्तर तक विकेंद्रीकृत करने के लिए "मोहल्ला/पिंड क्लीनिक" स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है। इस वर्ष सरकार 117 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने की योजना बना रही है जिसके लिए 77 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन प्रस्तावित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यह घोषणा करता हूँ कि इनमें से 75 मोहल्ला क्लीनिक 15 अगस्त, 2022 तक चालू हो जाएंगे।

58. **फरिश्ते:** समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण सड़क दुर्घटना में हताहत होना एक खेदजनक अनुभव है। 'आप' सरकार इस मुद्दे के प्रति बेहद संवेदनशील है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि सड़क दुर्घटना से पीड़ित हर व्यक्ति की जान बच सके। इसके लिए नई दिल्ली में फरिश्ते योजना की तर्ज पर पंजाब में एक योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को ले जा सकता है

और उन्हें किसी भी अस्पताल में भर्ती करा सकता है। सड़क हादसों के पीड़ितों का मुफ्त इलाज किया जाएगा और सारा खर्च पंजाब सरकार वहन करेगी और सहायता करने वाले व्यक्ति को भी सम्मानित किया जाएगा।

59. **एस्टेट मैनेजमैंट युनिट (ई.एम.यू) की स्थापना:** सर्वोत्तम इन-हाउस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हालांकि, इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माणकर्ताओं और संचालकों के बीच तालमेल न होने के कारण, इन सुविधाओं की निरंतरता और रखरखाव की अक्सर अनदेखी की जाती है। सरकार एस्टेट मैनेजमैंट युनिट (ई.एम.यू) स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है जो विशेष रूप से अस्पतालों/स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी उप-संरचना की जरूरतों के रखरखाव और संभाल पर ध्यान देगी और समयबद्ध तरीके से ऐसी गड़बड़ियों को दूर करेगी। इकाई शुरू में राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाएगी और बाद में इसे ऐसी सुविधाओं के पेशेवर प्रबंधन में शामिल किसी विशेष एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।

60. विभिन्न मौजूदा स्वास्थ्य योजनाओं जैसे ट्रॉमा सेंटरों की स्थापना, आयुष, आयुष्मान भारत-सरबत सेहत बीमा योजना, कैंसर राहत कोष योजना, कैंसर उपचार बुनियादी ढांचे का निर्माण और इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र में कमियों को दूर करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के अलावा अन्य में पर्याप्त आवंटन का प्रस्ताव किया जा रहा है।

61. आने वाले दो वर्षों में हमारी सरकार दो सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करेगी, एक पटियाला में और दूसरा फरीदकोट में। इसी तरह 2027 तक तीन और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाएंगे।

कृषि

माननीय अध्यक्ष महोदय,

62. पंजाब का कृषि क्षेत्र चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ, हमें किसानों की आय बढ़ाने की जरूरत है, दूसरी तरफ हम पंजाब को मरुस्थलीकरण से बचाने के लिए बाध्य हैं। भारत सरकार द्वारा किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, जब उन्होंने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सही आवाज उठाई, यह जग जाहिर है। मैं, अपनी सरकार की ओर से उनके संकल्प और दृढ़ता के लिए उन्हें सलाम करता हूँ; मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने असंवेदनशील सरकार का विरोध करते हुए अपनी जान गंवाई।

63. माननीय मुख्यमंत्री, सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने यह महसूस करते हुए कि यह कार्रवाई का समय है न कि केवल बात करने का, पहली बार पंजाब की कृषि को फिर से जीवंत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। कृषि क्षेत्र के लिए हमारी प्राथमिकता को दर्शाते हुए, मैं वित्त वर्ष 2022-23 में 11,560 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

64. **धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) :**अध्ययनों से पता चलता है कि धान की खेती की पोखर तकनीक की तुलना में डीएसआर पद्धति में 20% पानी बचाने की क्षमता है। किसानों को डीएसआर तकनीक के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही लागू करने वाले किसानों को 1500 प्रति एकड़ के वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है। उम्मीद है कि इस से आने वाले सालों में साकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और मैं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए डीएसआर के लिए 450 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ, ताकि किसानों को इस जल बचत तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

65. **मूंग की खेती पर एमएसपी' :**'आप' सरकार ने एमएसपी पर मूंग की खरीद का ऐतिहासिक फैसला किया है। यह किसानों को पारंपरिक 2 फसल चावल-गेहूँ चक्र से 3

फसलों की खेती के लिए प्रेरित करेगा। 65 दिनों की यह फसल किसानों की आय में वृद्धि करेगी, विविधीकरण को बढ़ावा देगी और पानी और मिट्टी का संरक्षण करेगी। इस उद्देश्य के लिए मार्कफ़ेड के कार्यान्वयन हेतु गैप-फ़ंडिग के रूप में 66 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) अपनी मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत पंजाब से मूंग की आंशिक खरीद के लिए सहमत हो गया है।

66. **पराली जलाने से रोकना:** हम जानते हैं कि किसानों द्वारा धान के पराली को जलाना अकारण नहीं है क्योंकि पैदावार की किसी भी हानि से बचने के लिए उन्हें अपने खेतों को अगली फसल के लिए सही समय पर तैयार करने की आवश्यकता है। पर यह वायु प्रदूषण का कारण बनता है, जो राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि पराली जलाना मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए यह सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक लक्षित कार्रवाई ही करेगी। मैं पराली जलाने की विभिन्न संभावनाओं और समाधानों का पता लगाने के लिए इस बजट में 200 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

67. **किसानों को मुफ्त बिजली:** मैं सभी अटकलों पर विराम लगाना चाहता हूँ। आप सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी रहने और कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प लेती है। मैं इस वित्त वर्ष 2022-23 में 6,947 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रख रहा हूँ।

68. बागवानी के बिना विविधीकरण की कोई भी बात अधूरी है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बागवानी के लिए आवंटन में दोगुनी वृद्धि करने के प्रस्ताव में इस सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से झलकती है।

69. इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग (आई.क्यू.एफ) तकनीक मौसमी फलों और सब्जियों को संरक्षित करने के लिए आदर्श है। आईक्यूएफ फलों और सब्जियों में फ्रीजिंग के बाद वही पोषक तत्व होते हैं जो उनके ताजे रूप में होते हैं। ग्राम वेरका, अमृतसर में एक नया क्विक फ्रीजिंग सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है I वित्त वर्ष 2022-23 में 7 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय का प्रस्ताव है। इसके अलावा माल्सियां, जालंधर में एक एकीकृत हाई-टेक सब्जी उत्पादन सह प्रौद्योगिकी प्रसार केंद्र के लिए, मैं इस वित्तीय वर्ष में शुरू करने के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूँ।

70. अपवाह जल के संरक्षण और उत्पादक उपयोग, तालाब के पानी, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के संवर्धन के लिए, 4 नई योजनाएं शुरू की गई हैं और मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन नई योजनाओं के तहत 21 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके अलावा, यह सरकार मौजूदा योजनाओं का समर्थन करना जारी रखेगी और उन्हें मिट्टी और जल संरक्षण के क्षेत्र में और मजबूत करेगी, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन भी शामिल है।

71. **कृषि का डिजिटलीकरण:** हमारे किसानों को शुरू से अंत तक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में व्यापक डिजिटलीकरण शुरू किया है। इसमें किसान प्रोफाइल का डिजिटलीकरण, उनके भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और उनकी उपज के लिए रिटर्न का ऑनलाइन हस्तांतरण शामिल है। यह कृषि पद्धति में आधुनिक तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने में किसानों की सहायता करेगा।

सहकारिता

72. सहकारिता ऐसे तंत्र हैं जो समुदायों की वृद्धि, सशक्तिकरण और समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। सहकारी एजेंसियों ने पंजाब में बैंकिंग, कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण सहित

विभिन्न क्षेत्रों में एक अद्वितीय भूमिका निभाई है। सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हुए, मैं 1,170 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 35.67% की वृद्धि है।

73. अपनी कवर क्षमता को बढ़ाने के लिए, सेंट्रल पूल गेहूँ स्टॉक के भंडारण के लिए नाबार्ड सहायता प्राप्त नई परियोजना के तहत 13 स्थानों पर मार्कफेड द्वारा नए गोदाम स्थापित किए जाएंगे और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 56 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की जा रही है। इसके अलावा, परेशानी रहित मूंग की खरीद के लिए मार्कफेड का समर्थन करने के लिए, सरकार पहले ही 400 करोड़ रुपए की राज्य गारंटी दे चुकी है, जिससे मार्कफेड इस उद्देश्य के लिए ऋण जुटा सके।

74. आप सरकार सभी क्षेत्रों के कल्याण के लिए समर्पित है और अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के विपरीत अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। सहकारी बैंकिंग संरचनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, इस सरकार ने पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक (पीएससीएडीबी) को राहत देने का फैसला किया है। मैं नाबार्ड को अपने ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए पीएससीएडीबी के लिए 688 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूँ।

वानिकी और वन्य जीवन

75. हमारी सरकार ने "शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह हरियावल लहर" नामक एक नई परियोजना शुरू की है, जिसके तहत शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी की 115वीं जयंती पर राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50,000 पौधे और 115 त्रिवेणी लगाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, इस उद्देश्य के लिए मौजूदा योजना "पंजाब समुदाय और सामाजिक वानिकी परियोजना" के तहत 10 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की जा रही

है। इसके अलावा, पनकंपा फंड के लिए 240 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 52 लाख पौधों को लगाया जाएगा।

रोजगार सृजन और कौशल विकास

अध्यक्ष महोदय,

76. हमारी सरकार रोजगारपरकता में सुधार लाने में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत है। हालाँकि, भीषण वास्तविकता हमारी यथास्थिति की धुंधली तस्वीर पेश करती है। वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, श्रम बल में पांच भारतीयों में से मुश्किल से एक भारतीय कुशल है। इसके अलावा, 2022 की भारत कौशल रिपोर्ट पंजाब के संबंध में एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। यह हमारी सरकार के साथ-साथ अन्य सरकारों के लिए भी एक वेक-अप कॉल है, क्योंकि युवाओं में कौशल की कमी हमें उनकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने से वंचित करती है।

77. 26,454 कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी घोषणा छलावा नहीं बल्कि हकीकत है। पंजाब कैबिनेट ने पहले ही विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 26,454 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिसमें से पंजाब पुलिस में विभिन्न पदों के लिए 10,000 नौकरियों की पेशकश की जाएगी जबकि शेष नौकरियों को अन्य विभागों में दिया जाएगा। हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता दिखाई देगी क्योंकि मैं इस संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 में 714 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूँ। साथ ही सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तावित नई पहलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार के एजेंडे का नेतृत्व करेगी, जो समान रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा।

78. अथक परिश्रम करने वाले हमारे ठेका कर्मचारियों को पिछली सरकारों ने नज़रअंदाज़

किया और उनके अथक प्रयासों की सराहना नहीं की गई। इस अमूल्य मानव संसाधन को देखते हुए और उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमारी सरकार ने 36,000 ठेका कर्मचारियों को नियमित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है। इस बजट में 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

79. उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा संस्थानों और सरकार की कौशल विकास पहलों के बीच तालमेल बनाने की जरूरत है। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, मेरा निवेदन है कि हर साल 250 कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्र पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के कौशल विज्ञान केंद्र द्वारा उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी डोमेन में कुशल होंगे। पंजाब के अप-स्किलिंग युवाओं के लिए, इस सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में एक सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए वैश्विक उद्योग भागीदारों और एल.टी.एस.यू (लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी) के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज (टी.टी.एल) को आमंत्रित किया है। यह पंजाब में निवेश लाने के अलावा, ईवी सेगमेंट के आगामी क्षेत्र में आवश्यक कौशल विकसित करने में अहम भूमिका अदा करेगा।

उद्योग और वाणिज्य

80. अध्यक्ष महोदय, हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि एक मजबूत विकसित औद्योगिक क्षेत्र राज्य के सतत आर्थिक विकास और समग्र विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है। मजबूत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज वाला यह उच्च मूल्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर कई गुना प्रभाव डाल सकता है जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और आय का स्तर बढ़ सकता है। हम अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का पोषण करना चाहते हैं और हमारे उद्योगपति भाइयों और बहनों द्वारा सामना किए जा रहे जमीनी स्तर के मुद्दों को हल करना चाहते हैं। मैं, हमारी सरकार की ओर से, पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का आश्वासन देता हूँ। इसे शुरू करने के लिए, मैं वित्त वर्ष 2022-

23 में बजटीय आवंटन 3,163 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूँ जो कि 2021-22 (बजट अनुमान) की तुलना में 48.06% की वृद्धि है।

81. **व्यापारी आयोग की स्थापना:** हमारी सरकार केवल व्यापारियों और कारोबारियों के सदस्यों के साथ एक विशेष आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है। यह आयोग निर्णय लेने और नीति निर्माण में सरकार के साथ सहयोग करेगा। इस का मूल सिद्धांत विचार नीतियों का निर्माण करना, मूल्य वृद्धि, रोजगार पैदा करना और पंजाब में औद्योगिक विकास को गति देने में सहायता करना है, जो इस क्षेत्र के लोग वास्तव में चाहते हैं ।

82. **औद्योगिक फोकल प्वाइंट:** मेरे बजट संबंधी पंजाब के विभिन्न हिस्सों के दौरे के दौरान उद्योगपतियों की प्रमुख मांगों में से एक राज्य में औद्योगिक फ़ोकल प्वाइंट्स को मजबूत करने की आवश्यकता थी। सबसे पहले, मैं अपने उद्योगपति भाइयों /व्यवसाय में लगे लोगों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूँ। उनकी मांग पर विचार करते हुए मैं औद्योगिक फ़ोकल प्वाइंट्स की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके अलावा, मैं घोषणा करता हूँ कि औद्योगिक पुनरुद्धार को बढ़ावा देने के लिए, अविकसित औद्योगिक संपदाओं और फोकल पॉइंट्स में अप्रयुक्त भूमि को प्रतिस्पर्धी दरों पर उद्योगों को उपलब्ध कराया जाएगा।

83. **पी.एस.आई.डी.सी/पी.एफ.सी को सहायता:** मैं पी.एस.आई.डी.सी और पी.एफ.सी को उनकी ऋण देनदारियों को चुकाने देने के लिए 250 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का प्रस्ताव रखता हूँ।

84. **फ़िनटेक सिटी:** अत्यंत महत्वपूर्ण आईटी क्षेत्र के भीतर फिनटेक क्षेत्र की विशाल क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मोहाली के पास एक फिनटेक सिटी स्थापित

करने का प्रस्ताव रखा है जहां फिनटेक, ब्लॉकचेन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

85. सरकार पंजाब को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रही है, जिसके लिए मोहाली में लगभग 490 एकड़ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा, कूमकलां, जिला लुधियाना में लगभग 950 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिस पर एक एकीकृत टैक्सटाईल पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है और राजपुरा में लगभग 1,100 एकड़ क्षेत्र में एक एकीकृत मैनुफ़ैक्चरिंग क्लस्टर भी स्थापित किया जा रहा है।

86. अंत में, मैं पंजाब के व्यवसायियों/उद्योगपतियों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप सरकार जमीनी स्तर के भ्रष्टाचार और कथित इंस्पेक्टर राज को पूरी तरह से खत्म करके डर के माहौल को खत्म करेगी और व्यापार के अनुकूल माहौल तैयार करेगी। वैट रिफंड के मुद्दे को छह महीने के भीतर हल करने का प्रस्ताव है और सरकार द्वारा औद्योगिक बिजली सब्सिडी प्रदान करना जारी रखा जाएगा जिसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 2,503 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत पात्र और योग्य औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत पूंजीगत सब्सिडी के वितरण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव है। राज्य को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में बनाने के लिए सरकार एक प्रगतिशील नई औद्योगिक नीति भी लाएगी।

शासन सुधार

अध्यक्ष महोदय,

87. सुशासन मॉडल में 8 प्रमुख विशेषताएं हैं। यह सहभागी, सर्वसम्मति उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, कुशल, न्यायसंगत और समावेशी होता है और कानून के शासन का पालन करता है। मैं पंजाब के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप सरकार ऊपर बताई गई सभी 8 विशेषताओं को पूरा करेगी। हम वादा करते हैं कि पंजाब के आम लोगों की जब भी सरकारी तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

88. सुशासन के वादे को पूरा करते हुए, आप सरकार ने सभी 320 सेवा केंद्रों और सभी सांझ केंद्रों के समय को सप्ताह के दिनों में दो घंटे बढ़ा दिया है और ये सेवा केंद्र रविवार को भी खुले रहेंगे। लोगों की शिकायतों के "मौके पर" निवारण के लिए हमारी सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम 'लोक मिलनी' शुरू किया गया है। सरकार ने पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सेवा वितरण सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प के साथ, पूरे पंजाब में संचालित सेवा केंद्रों के माध्यम से 100+ (सौ से अधिक) नई सेवाएं शुरू की हैं, जिस से ऐसी कुल सेवाओं की गिनती 425 हो गई है।

89. यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के खजाने से एक-एक पैसा समयबद्ध तरीके से लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे, हमारी सरकार एक मजबूत डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र (डीबीटी) तंत्र स्थापित करेगी, जो न केवल लीकेज को रोकेगा बल्कि शासन में दक्षता और प्रभावशीलता भी लाएगा।

90. पंजाब के हर जिले में सीएम फील्ड ऑफिस बनाए जाएंगे। इसके अलावा, यह सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ जिलों और सर्वश्रेष्ठ सब-

डिविजनों के लिए वार्षिक पुरस्कार स्थापित करने का प्रस्ताव करती है।

91. हम "डोरस्टेप डिलीवरी सर्विसेज" प्रणाली शुरू करने का भी प्रस्ताव रखते हैं जिससे नागरिक अपने घरों में आराम से विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उदाहरण के लिए, जाति/विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, नया पानी कनेक्शन/बिजली कनेक्शन इत्यादि जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं जल्द ही आपके घरों में पहुंचाई जाएंगी।

92. उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने की भी योजना है जो सरकारी कामकाज में आर्टीफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीनी प्रशिक्षण का अधिक से अधिक उपयोग करेगी। प्रशासन के कामकाज में अधिक उद्देश्य और जवाबदेही लाने हेतु; विभिन्न संकेतकों पर जिलों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक जिला प्रदर्शन डैशबोर्ड भी तैयार किया जाएगा।

93. सुशासन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, हम "स्टेट इंस्टीचियूट फ़ार स्मार्ट गवर्नेंस एंड फ़ाइनैंशियल मैनेजमेंट" नामक एक समर्पित संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं, जो राज्य सरकार को कार्य-प्रणाली में दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता लाने के बुजियादी उद्देश्यों के साथ एक समग्र दृष्टिकोण के आधार पर एक गवर्नेंस मॉडल विकसित करने में सहायता करेगी, जिससे 'शासन को दृश्यता' मिलेगी।

94. प्रामाणिक आंकड़ों के बिना सरकार स्टेथोस्कोप के बिना डॉक्टर की तरह है। पंजाब व्यापक राज्य डेटा नीति रखने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य डेटा-संचालित और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की संस्कृति का पोषण करना चाहता है। पंजाब राज्य डेटा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के माध्यम से, राज्य ई-गवर्नेंस सिस्टम के माध्यम से विभिन्न

कार्यक्रमों / योजनाओं की सेवा वितरण श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा। राज्य डेटा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य डेटा संचालन समिति का गठन किया जाएगा। जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए आने वाले दिनों में परिचालन दिशानिर्देश और मानक जारी किए जाएंगे। एक स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म (एस.डी.आई.पी) की योजना बनाई जा रही है जो डेटा साझा करने की संकुचित सोच की संस्कृति को रोकते हुए सभी विभागों में डेटा तक पहुंच और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगी।

आटे की होम डिलीवरी

95. हमारी सरकार गरीबों और दलितों के लिए बेहद संवेदनशील है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम / स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत गुणवत्तायुक्त भोजन देने के लिए 1.58 करोड़ रुपए लाभार्थियों को गेहूँ के स्थान पर अच्छी तरह से पैक किए गए आटे की डोर-टू-डोर डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। हम लाभार्थी के जीवन और आजीविका पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद करते हैं। लाभार्थियों को कतारों में खड़े होने, अपनी दैनिक मजदूरी खोने और अनाज को आटे में पिसाने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य इच्छित परिणामों में चोरी को रोकना, अनाज के पुनर्चक्रण को रोकना शामिल है। हमारी सरकार की इस विशेष पहल के लिए, मैं चालू वित्त वर्ष में 497 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूँ।

96. आटा-दाल योजना के कारण पनसप बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। धन की कमी के कारण, पनसप अपने 350 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण का भुगतान नहीं कर सका और परिणामस्वरूप एनपीए श्रेणी में चला गया। निगम को राहत प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने पनसप के एनपीए खातों के निपटान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 350 करोड़ रुपये के बेलआउट पैकेज का प्रस्ताव रखा है।

एन.आर.आई मामले

97. 'आप' सरकार का मानना है कि हमारे एन.आर.आई भाई-बहन राज्य के विकास में महत्वपूर्ण हितधारक हैं। एन.आर.आई समुदाय को विकासात्मक पहलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के मार्गदर्शन में, हमारी सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पूंजी निर्माण में सहायता के लिए जल्द ही "पंजाब सिक्खिया ते सेहत फ़ंड" नामक एक ट्रस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव रख रही है और वित्तिय वर्ष 2022-23 के दौरान इस ट्रस्ट को उचित प्रारंभिक धनराशि प्रदान की जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानी

98. सरकार महान स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और मैं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹16 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

रक्षा कल्याण

99. सरकार ने शहीदों और अन्य रक्षा कर्मियों, जिन्हों ने अपने प्राण देश के लिए न्योछावर कर दिए, को नमन करते हुए अनुग्रह सहायता को मौजूदा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा कल्याण के तहत 130 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है जो कि वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 11.00% की वृद्धि है।

100. हमारी सरकार भूतपूर्व सैनिकों को उचित सम्मान देती है और उनके कल्याण और पर्याप्त सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मोहाली में एक वृद्ध आश्रम बनाने

के लिए प्रतिबद्ध है।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले

101. हमारा मानना है कि पंजाब विशाल पर्यटन क्षमता वाला राज्य है, जिसका दुर्भाग्य से लाभ नहीं उठाया जा सका है। राजस्थान, केरल, गुजरात और अन्य राज्यों के विकास में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन पंजाब में इसका योगदान नगण्य है। हमारी सरकार पंजाब को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। उच्च पर्यटन क्षमता वाले स्थानों को विकसित करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास पहले ही शुरू हो चुके हैं। सरकार मुख्य रूप से पर्यावरण पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करेगी।

102. हमारे बीड़ और वनों में पर्यटन की विशाल संभावनाओं को स्वीकार करते हुए, हमारी सरकार ने सभी बीड़ और वनों को ईको-टूरिज्म के लिए विकसित करने का प्रस्ताव किया है जो कि पंजाब राज्य के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत साबित हो सकता है।

103. देश के महान सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए, सरदार भगवंत सिंह मान जी की यह सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रतिष्ठित कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों लाला लाजपत राय जी, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी और शहीद सुखदेव थापर जी की जयंती/शहीदी दिवस पर गांवों और शहरों के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

पुलिस का आधुनिकीकरण और कानून एवं व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय,

104. शांति और विकास साथ-साथ चलते हैं। पंजाब की लंबी शत्रुतापूर्ण अंतरराष्ट्रीय

सीमा है जो हमारे राज्य में अमन और शांति के लिए लगातार खतरा बनी हुई है। इसके अलावा, पंजाबियों को गैंगस्टरों से एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिन के बारे में एक दशक पहले कभी सुना नहीं था। हमारी सरकार निरंतर निगरानी बनाए रखने, लड़ने और मेरे राज्य की शांति, एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली बुरी ताकतों को मिटाने का दृढ़ संकल्प करती है। पंजाब में सक्रिय गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए एक पूर्ण गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और मुझे जल्द ही सकारात्मक परिणामों की उम्मीद है।

105. **पुलिस बलों का आधुनिकीकरण:** पुलिस बलों को मजबूत करने और उन्हें अपराध से निपटने के लिए नवीनतम गैजेट्स, प्रौद्योगिकी और उपकरणों से लैस करने के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए, चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 108 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। इस के अलावा 30 करोड़ रुपए की लागत से सभी ज़िलों में साइबर-क्राइम कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे।

106. अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को नई रणनीति बनानी होगी। **यह** जरूरी है कि पंजाब पुलिस के जवान **इस** नई रणनीति के बारे में सीखें। इसलिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस कर्मियों की क्षमता निर्माण की पहल की है।

107. **आम लोगों की सुरक्षा और सलामती:** हम अपने पुरुषों और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हमारे कार्यकाल के दौरान, पूरे राज्य को सीसीटीवी नेटवर्क से कवर किया जाएगा ताकि अपराध की जांच की जा सके और अपराधियों को पकड़ा जा सके। शुरू करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान क्रमशः मोहाली और पंजाब पुलिस महिला मित्तर केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

108. आज जेलें अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बन गई हैं। हमारी सरकार पहले ही पंजाब की जेलों में वीआईपी सेल को बंद करने की घोषणा कर चुकी है और जेल परिसर के अंदर विशेष सुविधाओं की पेशकश और उनका आनंद लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। इसके अलावा, साहिबज़ादा अजीत सिंह (एसएएस) नगर (मोहाली) में आधुनिक जिला जेल के निर्माण के लिए गांव कुरारा में 17.5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है और आरंभ में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।

सामाजिक कल्याण और न्याय

109. समावेशिता कल्याणकारी सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। समाज के सभी कमजोर वर्गों के हितों के उत्थान, संरक्षण और संवर्धन के प्रति हमारी गहरी निष्ठा है। आप सरकार वर्तमान में परिचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यक सभी प्रकार की सहायता देना जारी रखेगी। इसके अलावा, उन्हें और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। हम वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 7,437 करोड़ रुपए के बजटीय आंवटन का प्रस्ताव रखते हैं।

110. **सामाजिक सुरक्षा कवर :** सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए बजटीय आवंटन को 2021-22 (बजट अनुमान) के दौरान 4,071 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 में 28.12 लाख लाभार्थियों के कवरेज के साथ 31.23 लाख लाभार्थियों को कवर करने के लक्ष्य के साथ 4,720 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है।

111. माता तृप्ता महिला योजना: इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 46 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है।

112. **पोषण अभियान:** मैं 0-6 वर्ष की आयु के 11.20 लाख बच्चों और 1.80 लाख गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए वित्त वर्ष 2022-

23 के लिए 53 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव रख रहा हूँ।

113. **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:** मैं लगभग 2.50 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 640 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

114. **आशीर्वाद योजना:** इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है।

115. **प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई):** मैं वित्त वर्ष 2022-23 में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।

116. हमारी सरकार हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वित्त वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए 12,992 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.29% की वृद्धि है। यह बजटीय परिव्यय सामाजिक-आर्थिक विकास शुरू करने; रहने की स्थिति में सुधार; प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक हॉल, पोषण केंद्र, बिजली का विस्तार और सामान्य कार्य स्थल / सुविधा केंद्र आदि जैसी बुनियादी सेवाओं के प्रावधान में सहायता प्रदान करेगा।

117. इसके अलावा, सरकार ने साहिबजादा अजीत सिंह (एस.ए.एस) नगर में डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति से संबंधित कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी कार्यालय एक ही स्थान पर होंगे।

आधारभूत संरचना

118. किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का विशेष महत्व है। सड़क, बिजली, रेलवे, महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनें, स्कूल, अस्पताल आदि जैसे आर्थिक और

सामाजिक बुनियादी ढांचे किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वापेक्षाएँ हैं, और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए नए अवसर लाते हैं। मैं पंजाब में विभिन्न क्षेत्रों में नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 23,498 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।

ग्रामीण विकास और पंचायत

119. पंजाब की 63% आबादी अभी भी गांवों में रहती है, इसलिए समग्र रूप से "पिंडां दा विकास" सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,003 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया जा रहा है। पंचायत की जमीन को अवैध कब्जाधारियों से वापस दिलाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान पहले से ही चल रहा है। ताज़ा रिकार्डों के अनुसार लगभग 6100 एकड़ पंचायत भूमि से अवैध कब्जाधारियों को हटा दिया गया था, जिसकी कीमत कई हज़ार करोड़ रुपए है।

क. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 361 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2217.35 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए एक विशेष मरम्मत कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस के साथ ही, चल रही परियोजनाओं के तहत, शेष 4800.66 किलोमीटर सड़क पर नए निर्माण/चौड़ाकरण/विशेष मरम्मत के कार्यों को 757 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ पूरा करने का प्रस्ताव है।

ख. मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 600 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है।

ग. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के तहत, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए विकास के लिए 246 गांवों को कवर करने वाले 7 जिलों में 8 समूहों का चयन किया गया

था। मैं इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 145 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।

घ. प्रत्येक पंजाबी के अपने घर बनाने के सपने को साकार करने के लिए, हमारी सरकार ने 17,117 घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए मैं 2024 तक 'सभी के लिए आवास' के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 292 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।

च. मैं कंडी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 28,867 हेक्टेयर के सुधार के लिए चेक डैम, वायर क्रेट स्ट्रक्चर, रन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, स्टोन चिनाई रिटेनिंग वॉल, तालाबों का नवीनीकरण, रिसाव टैंक, फार्म तालाब आदि के निर्माण के लिए 20 रुपए करोड़ के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।

च. मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले गांवों के ठोस और तरल कचरे के उचित निपटारे और तालाबों की सफाई के उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

जल संसाधन

120. यह एक सच्चाई है कि पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के बिना पंजाब में कृषि की सफलता संभव नहीं है। वर्तमान में, भूजल सिंचाई के साथ सतही जल सिंचाई का विस्तार, कायाकल्प और मिश्रण करने की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए सतही और भूजल के इस विवेकपूर्ण मिश्रण में जल भराव और जल की कमी दोनों समस्याओं को हल करने की क्षमता है। मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 2,547 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

क. **शाहपुर कंडी बांध परियोजना:** रावी नदी पर मुख्य बांध के शेष कार्य के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 189 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय प्रदान किया जा रहा है और इसके वर्ष 2023-24 तक पूरा होने की उम्मीद है। पूरा होने पर यह 206 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 1042 मिलियन यूनिट हाइड्रो-

इलेक्ट्रिक उत्पन्न करेगा और अपर बारी दोआब नहर प्रणाली के तहत 37,173 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के साथ-साथ 1.18 लाख हेक्टेयर की गहन सिंचाई करेगा।

ख. **राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग:** वित्त वर्ष 2022-23 में उन कार्यों के निष्पादन के लिए 780 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय प्रस्तावित है, जिनके जून, 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह राजस्थान फीडर से 752 क्यूसेक और सरहिंद फीडर से 256 क्यूसेक की सीपेज हानि को बचाएगा और पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में जलभराव को रोकने में भी मदद करेगा।

ग. **कोटला शाखा भाग- II परियोजना:** इस परियोजना के तहत जलस्रोतों की लाइनिंग के लिए इस बजट में 18 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। यह कार्य 31.03.2025 तक पूरा होने की उम्मीद है जिससे जिला बठिंडा, मानसा, संगरूर और बरनाला में 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि को बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

घ. **जलनिकास:** रावी और उसकी सहायक नदियों उझ पर भारत-पाक सीमा पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों को "नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों" के तहत निष्पादित किया जा रहा है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वाजिब परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

121. राज्य सरकार राज्य के सभी घरों में पाइप वितरण नेटवर्क और स्वच्छता सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वित्तीय वर्ष में 2374 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2021-22 (आरई) की तुलना में 48.94% की वृद्धि है। कुल मिलाकर 12009 गांवों में से 98% गांवों को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी) कवरेज के साथ **'हर घर जल'** गांव घोषित किया गया है।

क. **आर्सेनिक-सह-लौह निष्कासन संयंत्र:** आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में दीर्घकालिक

शमन उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, 400 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी मद्रास द्वारा 72 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में नैनो सामग्री का उपयोग करके सोखने की तकनीक पर आधारित 51 आर्सेनिक-सह-लौह निष्कासन संयंत्रों को वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू किया जाएगा तथा इस योजना के अंतर्गत आने वाली शेष 62 बस्तियों में कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

ख. **सामुदायिक जल शोधन संयंत्र:** सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (सी.डब्ल्यू.पी.पी) और आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में विकेन्द्रीकृत घरेलू शोधक के माध्यम से पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने और राज्य के फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में फ्लोराइड हटाने की स्थापना के लिए गतिविधियों हेतु 51 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है।

ग. **मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव :** जल आपूर्ति योजनाओं पर बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए 18 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है और 10 करोड़ रुपए की लागत से साहिबजादा अजीत सिंह (एस.ए.एस) नगर में जल भवन का निर्माण भी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है।

सड़कें व पुल

122. "जनता बजट" सर्वेक्षण के दौरान बठिंडा की मेरी यात्रा के समय, जनता नगर और मुल्तानिया रोड पर पुलों की मांग को मेरे ध्यान में लाया गया था। मैं वित्त वर्ष 2022-23 में भटिंडा में पुलों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि का आश्वासन देता हूँ।

123. सरकार का कंडी क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है जो चंडीगढ़ से पठानकोट तक

फैला है। शिवालिक के साथ चंडीगढ़ से पठानकोट तक एक राजमार्ग विकसित करने का प्रस्ताव है, जो इस उप-पर्वतीय कंडी क्षेत्र में नए अवसर लाएगा और जिसके लिए सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) और भारत सरकार के साथ इस मामले को उठाएगी।

124. हमारी सरकार नई सुरक्षित और टिकाऊ सड़कों और पुलों के रूप में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी और मौजूदा पुलों की संभाल के लिए भी काम करेगी। इस क्षेत्र में फिजूलखर्ची को रोकने, बाजार की विफलता को खत्म करने और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में मौजूदा सड़कों, पुलों और भवन के नए निर्माण और रखरखाव के लिए 2,102 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है।

परिवहन

125. पंजाब में परिवहन क्षेत्र शक्तिशाली राजनेताओं द्वारा स्थापित एकाधिकार, दोषपूर्ण नीतियों के कारण राज्य के राजस्व की हानि और अक्षम और कमजोर राज्य परिवहन निगमों के लिए बदनाम रहा है। हमारी सरकार राज्य में तथाकथित परिवहन माफिया को समाप्त करने के साथ-साथ आम लोगों को सुरक्षित और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने का वचन देती है। हम इस क्षेत्र में गुणवत्ता और समानता लाने के लिए काम करेंगे और नए तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी संचालित वाहनों को बढ़ावा देंगे ताकि यात्रियों को आराम और पर्यावरण को राहत मिल सके। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 45 नए बस स्टैंडों का निर्माण और पनबस और पीआरटीसी के 61 बस स्टैंडों का नवीनीकरण शुरू किया जाएगा।

स्थानीय सरकार

126. अध्ययनों से पता चलता है कि भारत की शहरी आबादी 2050 तक दोगुनी हो जाएगी और पंजाब के भारत में सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाले राज्यों में से एक होने की उम्मीद है। यह सरकार शहरी पंजाब की बढ़ती आकांक्षाओं से अवगत है और इसलिए हमारे शहरों/कस्बों को हमारे आर्थिक और विकासात्मक ढांचे के केंद्र में रखेगी। हम अपने शहरों को आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन का स्थायी इंजन, यानी द हार्बिंगर्स ऑफ मॉडर्न पंजाब, बनाना चाहते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में 6,336 करोड़ रुपए का आवंटन प्रदान किया जा रहा है। इस सरकार का एक उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, उन्हें अपनी कार्यशैली में आत्मनिर्भर और पेशेवर बनाना भी है।

क **स्मार्ट सिटीज़ मिशन:** लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और पवित्र शहर सुल्तानपुर लोधी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और इस वर्ष 1,131 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया जा रहा है।

ख. **कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत):** अमृत मिशन के तहत पंजाब के 16 शहरों के लिए 2,785 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जालंधर और पटियाला के लिए 24x7 सतही जल आपूर्ति योजनाओं सहित प्रमुख परियोजनाओं को शुरू करने के लिए इस वर्ष 1,100 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया जा रहा है; बुड्डा नाला, लुधियाना का कायाकल्प; बड़ी नदी और छोटी नदी, पटियाला का कायाकल्प; अन्य के अलावा विश्व बैंक के वित्त पोषण की सहायता से अमृतसर और लुधियाना में नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना।

ग. **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी:** मैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित इस मिशन के तहत खाद बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बागवानी अपशिष्ट प्रबंधन और जीव अमृत / बैक्टीरियल कल्चर गतिविधियों को शुरू करने के लिए 180 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ;

आवास और शहरी विकास

127. अति शहरीकरण के इस युग में शहरी नियोजन विकास की मुख्य आवश्यकता है। अनियोजित शहरी विकास एक अभिशाप बन जाता है जो शहरी समूहों को अराजक स्थानों में तबदील कर देता है। नियोजित शहरी विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 79 शहरों को कवर करते हुए 44 मास्टर प्लान अधिसूचित किए गए हैं और आगे 70 मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। यह सरकार शहरी परिवहन को प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनाते हुए शहरी गतिशीलता योजनाओं पर काम करेगी।

128. हमारी सरकार का मानना है कि मूल नागरिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच पंजाब का अधिकार है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसलिए, हमारे शहरों में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हम चरणों में 25,000 ईडब्ल्यूएस घरों का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं।

129. हितधारकों की आसानी के लिए इस क्षेत्र में ई-गवर्नेंस पहलकदमियां की जा रही हैं; ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, संपत्तियों की जी.आई.एस मैपिंग, संपत्ति रिकॉर्ड की स्कैनिंग जैसी आई.टी. पहलकदमियां चल रही हैं, जिससे इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

राजस्व वृद्धि

अध्यक्ष महोदय,

130. आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां राजकोषीय समझदारी अधिशेष राजस्व सृजन की मांग करती है, खासकर तब जब जी.एस.टी मुआवजा 30 जून को बंद हो जाएगा; हमें अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाते हुए हमारे राजस्व व्यय को कम करने और उन नीतियों को लागू करने की ज़रूरत है जिनके परिणामस्वरूप निरंतर जीडीपी की वृद्धि होगी, जिससे राज्य का समग्र विकास होगा।

131. इस आधार को ध्यान में रखते हुए, मैं इस वर्ष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने व्यय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजस्व रोडमैप के साथ शुरुआत करूंगा। यह पिछले बजटों की तुलना में एक स्वागत योग्य प्रयत्न है, जहां सरकारों ने वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के सहारे के बिना केवल योजनाओं और सैद्धांतिक बजट आवंटन की घोषणा पर ध्यान केंद्रित किया था। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने पहले ही राजस्व वृद्धि के उपाय शुरू कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2022-23 में हमारी राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.08% की वृद्धि होगी, जिस से राज्य के खजाने में 95,378 करोड़ रुपए आएंगे। **इस महत्वाकांक्षी विचारधारा की विशेषता यह है कि यह सब पंजाब के लोगों पर कोई नया टैक्स लगाए बिना किया जाएगा।**

132. नई आबकारी नीति एक "गेम चेंजर" नीति होगी, जो वर्षों से इस क्षेत्र में विकसित एकाधिकार/कुलीनतंत्र को तोड़ देगी। हम अपने उत्पाद शुल्क राजस्व को 9,648 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि वर्ष 2021-22 के अनुमानों के मुकाबले 56% की भारी वृद्धि होगी। जीएसटी वसूली में खामियों को दूर करने के प्रयास पहले से ही

जारी हैं, मुझे जीएसटी वसूली में 27% का उछाल आने की उम्मीद है। वर्ष 2022-23 में, जो राजकोष में लगभग 4,350 करोड़ रुपए का योगदान देगा।

133. हमारी सरकार गैर कर राजस्व क्षेत्र में भी वृद्धि दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है। खनन सहित विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतियों से राज्य के गैर कर-राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 636 करोड़ रुपए अर्थात 11% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

134. इसके अलावा, केंद्र से केंद्रीय करों और सहायता अनुदानों का हिस्सा क्रमशः 14,757 करोड़ रुपए और 28,731 करोड़ रुपए अनुमानित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

135. नेक इरादे चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं, अपनी पार्टी के हर सदस्य की ओर से जोर देकर कहता हूँ कि हमारे इरादे पवित्र व नेक हैं। इस बजट में समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया है जिसमें श्रमिक, किसान, युवा, छोटे व्यवसायी, उद्योगपति, भूतपूर्व सैनिक, वंचित लोग, महिलाएं, बच्चे और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं। हम अपने पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के अनुरूप अपने सपनों का पंजाब बनाने के लिए दिन-रात काम करेंगे। आगे की राह कठिन हो सकती है, लेकिन हमारा संकल्प किसी भी बाधा से दृढ़ है। चूंकि ऊंची और बड़ी इमारतों को मजबूत नींव पर ही बनाया जा सकता है, आज मैंने जो बजट पेश किया है, वह हमारे पंजाबी समाज और अर्थव्यवस्था की बुनियादी नींव पर केंद्रित है।

136. मैं पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री, सरदार भगवंत सिंह मान जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उनके दृढ़ समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा, मैं इस सम्मानित सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पंजाब

की बेहतरी के लिए इस विधानसभा में विचारशील चर्चा और साकारात्मक बातचीत की उम्मीद करता हूँ।

137. अंत में, मैं वित्त और योजना विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने इस जटिल कार्य को दक्षता और सटीकता के उच्च मानकों के साथ पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। सरकार की ओर से, हम महालेखाकार, पंजाब के कार्यालय से प्राप्त नियमित अंतर्दृष्टि के आभारी हैं, जिसने हमें अपनी प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद की है।

138. इसी के साथ, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए इस गौरवशाली सदन की सराहना करता हूँ और गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिखे गए सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ समाप्ति करना चाहूँगा, जिसने मुझे सदा प्रेरित किया है और भविष्य में भी हमारी सरकार का कठिन समय में मार्गदर्शन करती रहेंगी।

देह सिवा बरु मोहि इहै सुभ करमन ते कबहूँ न टरों॥
न डरों अरि सो जब जाइ लरों निसचै करि अपुनी जीत करों ॥

जय हिन्द